चाबहार परियोजना

प्रलिम्सि के लयि:

फरज़ाद-बी गैस क्षेत्र, इस्लामकि रविोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे लाइन, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षणि परविहन गलयिारा, वन बेल्ट वन रोड

मेन्स के लयि:

चाबहार बंदरगाह से संबंधति भारतीय हति और चुनौतयिाँ

चर्चा में क्यों

हाल ही में ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन (Port and Maritime Organisation) ने **चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे लाइन** हेतु लोकोमोटवि और सग्निलगि उपकरण उपलब्ध कराने हेतु भारत से अनुरोध कयिा है।

- संयुक्त राज्य अमेरकिा द्वारा लगाए गए प्रतबिंधों के कारण ईरान को इन उपकरणों की प्रत्यक्ष खरीद में कठनिाई का सामना करना पड़ रहा है।
- ईरान ने भारत से 150 मलियिन अमरीकी डालर क्रेडटि लाइन को भी सक्रयि करने के लयि कहा है जो वर्ष 2018 में ईरानी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत द्वारा इसे प्रदान की गई थी।

प्रमुख बदिु

पृष्ठभूमि:

- मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानस्तिान ने एक त्रपिक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कयि जसिके तहत ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हुए समुद्री परविहन के लयि क्षेत्रीय हब के रूप में पारगमन और परविहन गलयिारा स्थापति करने की परकिल्पना की गई।
- अफगानस्तिान और मध्य एशयि के लयि एक वैकल्पकि व्यापार मार्ग के रूप में चाबहार बंदरगाह से ज़ाहेदान (अफगानस्तिान सीमा) तक एक रेल लाइन का नरि्माण भी इस परविहन गलयिारे का एक हस्सिा था।
- राज्य के स्वामतिव वाली **भारतीय रेलवे नरि्माण लमिटिेड (Indian Railways Construction Ltd.)** ने सभी प्रकार की सेवाएँ, अधरिचना कार्य और वत्तिपोषण (लगभग 1.6 बलियिन अमरीकी डॉलर) प्रदान करने के लयि ईरानी रेल मंत्रालय के साथ एक**समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)** पर हस्ताक्षर कयि।

इस परियोजना से भारत के अलग होने के कारण:

- **ईरान का रुख:**
  - जुलाई 2020 में, ईरान ने परियोजना की शुरुआत और वत्ति पोषण में देरी का हवाला देते हुए, स्वयं रेल लाइन नरि्माण करने का फैसला कयि।
- **भारत का रुख:**
  - IRCON ने नरि्माण-स्थान नरीक्षण एवं व्यवहार्यता रपिोर्ट को पूरा कयि और ईरानी पक्ष द्वारा नोडल प्राधकिरण नयिुक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था।
  - यद्यपि इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरकिा से एक वशिेष छूट प्राप्त है फरि भी भारत नरि्माण कंपनी से समझौता करने में संकोच कर रहा है क्योंकि यह कंपनी **इस्लामकि रविोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps)** के साथ संबंध रखती है जो प्रतबिंधों के दायरे में आती है।
    - IRGC एक हार्ड-लाइन बल है जो ईरान के नयिमति सशस्त्र बलों के समानांतर अपनी सैन्य अवसंरचना को संचालति करता है। अप्रैल 2020 में, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह नूर इसने ही लॉन्च कयि था।
    - संयुक्त राज्य अमेरकिा द्वारा प्रतबिंध लगाए जाने के भय ने ईरान के **फरज़ाद-बी गैस क्षेत्र परियोजना** में भारतीय हति को भी प्रभावति कयि है।

भारत के लिये चाबहार पोर्ट का महत्व:

- **व्यापार:** इसे तीन भागीदार देशों के साथ-साथ अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिये सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जा रहा है।
- **सुरक्षा:** चीन वन बेल्ट वन रोड **(One Belt One Road)** परियोजना के तहत अपने स्वयं के **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative)** को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान में चीनी निवेश के साथ विकसित किये जा रहे ग्वादर बंदरगाह के प्रत्युत्तर के रूप में भी काम कर सकता है।
- **कनेक्टिविटी:** भविष्य में, चाबहार परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा **(International North South Transport Corridor)** रूस तथा यूरेशिया के साथ भारतीय संपर्क/कनेक्टिविटी का अनुकूलन कर एक दूसरे के पूरक होंगे।

परिदृश्यों का विकास:

- भारत और ईरान दोनों का ध्यान इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावी परिणामों पर है ताकि नए परिणाम आने के बाद शायद प्रतिबंधों में कुछ छूट दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से विकसित करने का अवसर दे सके।
- भारत, चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते (400 बिलियन अमरीकी डॉलर) पर भी नज़र बनाए हुए है जिसमें चाबहार के अन्य हिस्सों (जिसमें मकरान तट के साथ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और तेल संरचना शामिल हैं) के विकास हेतु वित्तपोषण किया जा सकता है।

आगे की राह

- ऐसे विश्व में जहाँ कनेक्टिविटी को नई मुद्रा के रूप में देखा जाता है, भारत इस परियोजना को खो सकता है तथा यह परियोजना किसी दूसरे देश, विशेष रूप से चीन को मिल सकती है। इसलिये, भारत को इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक संतुलित नीति पर काम करने की आवश्यकता है।
- एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, भारत केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रह सकता है और एक शांतिपूर्ण तरीके से विकसित पड़ोस (ईरान-अफगानिस्तान) न केवल व्यापार तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिये बेहतर है, बल्कि एक महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chabahar-project